



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 264]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 20, 2000/कार्तिक 29, 1922

No. 264]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 20, 2000/KARTIKA 29, 1922

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क निदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2000

विषय : चीन जनवादी गणराज्य के भूल के अथवा वहां से निर्यातित ड्राई बैटरी के आयातों के संबंध में
पाटनरोधी जांच शुरु करना

फा. सं. 53/1/2000-डीजीएडी.—निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) ने विश्वस्त स्रोतों से सूचना प्राप्त की है कि चीन जनवादी गणराज्य (जिसे इसके बाद संबद्ध देश कहा गया है) से ड्राई बैटरी (जिसे इसके बाद संबद्ध वस्तु कहा गया है) का भारत में पिछले 6 महीनों से पाटन किया जा रहा है।

1. विचाराधीन उत्पाद: विचाराधीन उत्पाद ड्राई बैटरियां हैं (विशेष रूप से प्राइमरी पेन्सिल सैल और बैटरियां) जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की अनुसूची -I के सीमाशुल्क उपशीर्ष 850610 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं, इस उत्पाद का उपयोग टार्च, ट्रांजिस्टर, खिलोने, कैमरा, टेपरिकार्ड, सीडी प्लेयर, लेपटाप पी सी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक और इलैक्ट्रिकल गेजेट में किया जाता है। बैटरियां विभिन्न साइजों में उपलब्ध हैं, तथापि, पेपर तथा मेटल (हेवी ड्यूटी तथा सुपर हेवल ड्यूटी दोनों) दोनों में लिपटे आर 6 (एए) रुप जांच के दायरे में आते हैं। नियम 2 घ के अर्थों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित सामान संबद्ध देश से आयातित वस्तु के 'समान वस्तु' है। आगे यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी प्रकार बाध्यकारी नहीं है।

2. पाटन: इस बात के प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त साक्ष्य है जो यह संकेत करते हैं कि सम्बद्ध देश में सम्बद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य उस कीमत से पर्याप्त रूप से अधिक है जिस पर ये भारत को निर्यात की गई जिससे पता चलता है कि सम्बद्ध वस्तु सम्बद्ध देश के निर्यातकों द्वारा पाटित की जा रही है।

3. क्षति एवं कारणात्मक संबंध: विभिन्न मापदण्ड जैसे आयातों की मात्रा और कीमतों में कटौती प्रथम दृष्ट्या यह संकेत करते हैं कि घरेलू उद्योग को संबद्ध सामानों के पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

4. जांच शुरू करना और जांच अवधि: उपरोक्त पैराग्राफ को देखते हुए प्राधिकारी सीमा शुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर शुल्क अथवा अतिरिक्त शुल्क का आकलन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 के नियम 5(4) के अनुसार संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों की कथित डम्पिंग होने, उसकी मात्रा तथा उसके प्रभाव की पाटनरोधी जांच आरंभ करते हैं। जांच अवधि 1.4.2000 से 30.9.2000 तक की है।

5. सूचना प्रस्तुत करना: संबंधित ज्ञात निर्यातक तथा आयातक और घरेलू उद्योग संगत सूचना को निर्धारित प्रश्नावली, जो वेबसाइट <http://commin.nic.in/doc> पर उपलब्ध है, निर्धारित ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं और अपने विचारों से निम्नलिखित को अवगत करा सकते हैं-

श्री एल.वी. सप्तऋषि
निर्दिष्ट प्राधिकारी
(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)
भारत सरकार
वणिज्य मंत्रालय
उद्योग भवन
नई दिल्ली-110011

6. नई दिल्ली स्थित संबद्ध देश के दूतावास को भी संबद्ध देश के निर्यातकों/उत्पादकों की संबंधित प्रश्नावली भेजी जा रही है ताकि वे जांच आरंभ करने की इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र में सूचना दायर कर सकें।

7. कोई अन्य हितबद्ध पक्ष भी जांच से संबंधित अपना अनुरोध निर्धारित रूप एवं निर्धारित ढंग (उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध और इस महानिदेशालय में भी उपलब्ध) में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

8. अगोपनीय सारांश: सभी हितबद्ध पक्षों को पाटनरोधी नियम 7(2) के अनुसार किसी गोपनीयता के बारे में प्रदत्त किसी सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करना चाहिए। यह सूचना नियम 7(1) और (2) के अनुसार स्वीकार की जाएगी।

9. सार्वजनिक फाइल: नियम 6(7) के अनुसार रुचि रखने वाली कोई भी पार्टी उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकती है जिसमें अन्य हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश रखे गए हैं।

10. यदि कोई हितबद्ध पार्टी आवश्यक सूचना जुटाने से मना करती है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराती है या महत्वपूर्ण ढंग से जांच में बाधा डालती है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकता है।

एल. वी. सप्तऋषि, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2000

Subject: Initiation of anti dumping investigation concerning imports of Dry Batteries originating in or exported from PR China

F. No. 53/1/2000-DGAD.—The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority) has received information from reliable sources that dry batteries (hereinafter referred to as subject goods) from People's Republic of China (hereinafter referred to as subject country), is being dumped in India over the last six months.

1. **Product Under Consideration**: The product under consideration is dry batteries (specifically primary pencil cells and batteries) which is classified under custom sub-heading 850610 of Schedule I of the Customs Tariff Act, 1975. The product is used in torches, transistors, toys, cameras, tape recorders, CD players, laptop PCs and other electronic and electrical gadgets. The batteries are available in various sizes, however, R6 (AA) both in paper and metal (both heavy duty and super heavy duty) jacketed form are within the scope of investigation. The goods manufactured by the domestic industry are 'like articles' to the goods imported from the subject country within the meaning of Rule 2(d). The classification is indicative only and is in no way binding on the determination of the product.

2. **Dumping:** There is sufficient prima facie evidence indicating that the normal value of the subject goods in the subject country is significantly higher than the prices at which it has been exported to India suggesting that the subject goods are being dumped by the exporters of the subject country.
3. **Injury & Causal Link:** Various parameters viz., volume of imports and price suppression, prima facie indicate that the domestic industry has suffered material injury on account of dumping of the subject goods
4. **Initiation and Period of investigation:** The Authority in view of the foregoing paragraphs initiates anti dumping investigation into the existence, degree and effect of alleged dumping of subject goods originating in or exported from the subject country in accordance with Customs Tariff (Amendment) Act 1995 and Rule 5(4) of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995. The period of investigation is 1.4.2000 to 30.9.2000.
5. **Submission of Information:** The exporters and importers known to be concerned and domestic industry may submit the relevant information in the form and manner prescribed in the questionnaire and available at the website <http://commin.nic.in/doc> and may make their views known to –

Shri L V Saptharishi
Designated Authority
(Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties)
Government of India
Ministry of Commerce
Udyog Bhavan, New Delhi-110011

6. The Embassy of the subject country in New Delhi is also being supplied with the questionnaire relevant to the exporters/producers in the subject country so as to enable them to file the information in the prescribed format within forty days from the date of publication of this Initiation Notification.

7. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner (available at the above website and also with this Directorate) within forty days from the date of publication of this Notification.
8. Non confidential summary: All interested parties must provide a non confidential summary of any information provided on a confidential basis in terms of Anti Dumping Rule 7(2). This information will be subject to acceptance in terms of Rules 7(1) and (2).
9. **Inspection of Public File**: In terms of Rule 6(7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.
10. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority

3183 GI/2022

